शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 21 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 16 – 23 मई 2022 मूल्य पांच रूपए

ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ चर्चित शिकायत पर कारवाई क्यों नहीं

सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक लंबे अरसे से विवादों का केंद्र चला आ रहा है। विभाग को लेकर पहली चर्चा उस समय शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नाम लिखा एक पत्र वायरल हुआ। इस पत्र के तथ्यों पर कोई जांच करने की बजाय सरकार ने इसके लेखक का पता लगाने को प्राथमिकता दी। कई लोगों पर शक किया गया। शैल भी शक के दायरे में रहा और अंततः धूमल शासन में मंत्री रहे रविन्द्र रवि के खिलाफ इस संबंध में एक मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले का अंतिम परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। इसके बाद सोलन से एक ऑडियो वायरल हुआ। इस पर मामला दर्ज हुआ तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी तक हुई। स्वास्थ्य मंत्री को बदलकर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मामले का अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है। फिर पी.पी. किटस और सैनिटाइजर खरीद पर सवाल उठे। सैनिटाइजर खरीद पर सचिवालय के एक अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसका भी परिणाम आना शेष है।

लेकिन इन सारे मामलों के साथ एक और गंभीर तथ्य यह घटता रहा कि हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल फेल होने के समाचार आते रहे हैं। विधानसभा में इस आश्य के प्रश्न आये। सरकार ने जवाब में दवाइयों और निर्माता कंपनियों के नामों सहित पूरा विवरण पटल पर रखा। लेकिन इस पर कारवाई के नाम पर यही आया कि निर्माताओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिये गये। शो कॉज नोटिस के बाद क्या कारवाई हुई आज तक सामने नहीं आया है। जबकि सैंपल फेल होने के किस्से अब तक जारी हैं। संयोगवश विधानसभा में आये सवाल लिखित जानकारी आने तक ही सीमित रहे हैं। बद्दी देश का एक बड़ा फार्मा हब है। बड़े-बड़े दवा निर्माता यहां पर हैं। हिमाचल में बनी हुई एक दवाई के सेवन से जम्मू में कुछ बच्चों की मौत होने तक का मामला घट चुका है। इस पर एक अपराधिक मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन इसका भी अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है।

दवाई जीवन रक्षक होती है। जब उसके निर्माण में उसकी गुणवत्ता के मानकों की ही पालना नहीं होगी तो शायद इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता। ऐसे अपराधियों के खिलाफ यदि कारण बताओ नोटिस से आगे कारवाई न बढ़े तो क्या इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह नहीं माना जाना चाहिये। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना दवा नियंत्रक की जिम्मेदारी होती है। दवाइयों की कीमतें किस गति से बढ़ाई जा रही हैं और इसमें फार्मा कंपनियां किस तरह आचरण करती हैं इसका जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार अपनी आत्म कथा में कर चुके हैं। नागपुर में एक एनजीओ साथी कि 40 पन्नों की रिपोर्ट में भी फार्मा कंपनियों की भूमिका को लेकर बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिमाचल में दवा नियंत्रक रहे शेर सिंह का मामला भी सभी जानते हैं। दवाइयों की खरीद में किस तरह कितने कमीशन का आदान-प्रदान होता है इसका खुलासा मण्डी में हुई खरीद पर कैग रिपोर्ट में आ चुका है। जब नड्डा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी इस खरीद पर लंबा चौड़ा मामला घट चुका है तब भी स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी हुई थी।

इस परिदृश्य में आज जो आठ पन्नों की एक शिकायत दवा नियन्त्रक मरवाह के खिलाफ मीडिया तक पहुंची है उस पर सरकार द्वारा अब तक कोई कारवाई न किया जाना अपने में कई सवाल खड़े कर देता है। एक एम.सी. जैन द्वारा प्रधानमंत्री सहित एक दर्जन अधिकारियों नेताओं को भेजी इस शिकायत में बहुत गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की सत्यता सामने आनी चाहिए। जिस एम सी जैन के नाम से यह शिकायत मीडिया तक पहुंची है वहीं पर यह शिकायत सरकार और उसकी एजेंसियों तक भी पहुंची होगी। लेकिन इस पर अब तक किसी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया जारी न होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में इस शिकायत में दर्ज तथ्यों की सत्यता पर कुछ भी न कहते हुये इसे यथास्थिति पाठकों के सामने रखना सरोकारी पत्रकारिता का धर्म हो जाता है।

यह है एम.सी.जैन की शिकायत

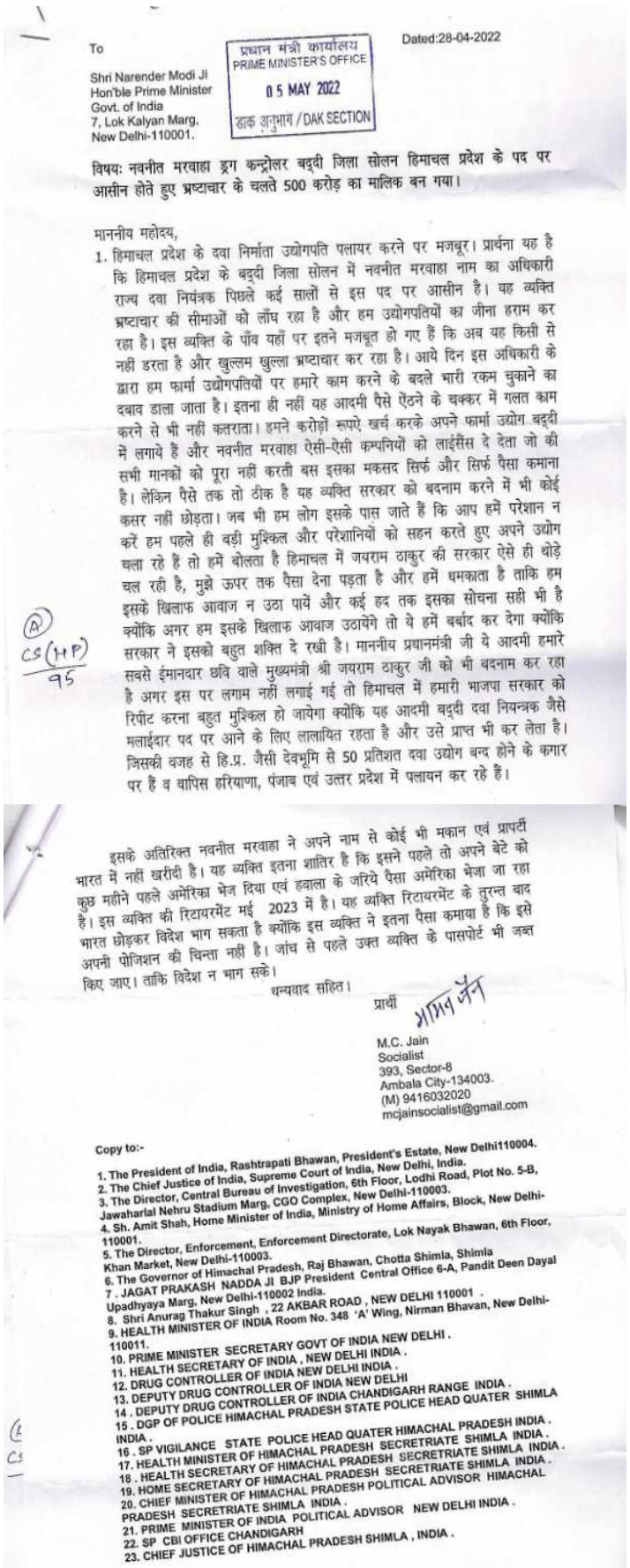

To

Shri Narender Modi Ji
Hon'ble Prime Minister
Govt. of India
7, Lok Kalyan Marg,
New Delhi-110001.

प्रधान मंत्री कार्यालय PRIME MINISTER'S OFFICE 05 MAY 2022 डाक अनुभाग / DAK SECTION

Dated:28-04-2022

विषयः नवनीत मरवाहा ड्रग कन्ट्रोलर बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के पद पर आसीन होते हुए भ्रष्टाचार के चलते 500 करोड़ का मालिक बन गया।

माननीय महोदय,

1. हिमाचल प्रदेश के दवा निर्माता उद्योगपति पलायर करने पर मजबूर। प्रार्थना यह है कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला सोलन में नवनीत मरवाहा नाम का अधिकारी राज्य दवा नियंत्रक पिछले कई सालों से इस पद पर आसीन है। यह व्यक्ति भ्रष्टाचार की सीमाओं को लाँघ रहा है और हम उद्योगपतियों का जीना हराम कर रहा है। इस व्यक्ति के पाँव यहाँ पर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब यह किसी से नहीं डरता है और खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर रहा है। आये दिन इस अधिकारी के द्वारा हम फार्मा उद्योगपतियों पर हमारे काम करने के बदले भारी रकम चुकाने का दबाव डाला जाता है। इतना ही नहीं यह आदमी पैसे ऐंठने के चक्कर में गलत काम करने से भी नहीं कतराता। हमने करोड़ों रूपऐ खर्च करके अपने फार्मा उद्योग बद्दी में लगाये हैं और नवनीत मरवाहा ऐसी-ऐसी कम्पनियों को लाईसैंस दे देता जो की सभी मानकों को पूरा नहीं करती बस इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन पैसे तक तो ठीक है यह व्यक्ति सरकार को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। जब भी हम लोग इसके पास जाते हैं कि आप हमें परेशान न करें हम पहले ही बड़ी मुश्किल और परेशानियों को सहन करते हुए अपने उद्योग चला रहे हैं तो हमें बोलता है हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ऐसे ही थोड़े चल रही है, मुझे ऊपर तक पैसा देना पड़ता है और हमें धमकाता है ताकि हम इसके खिलाफ आवाज न उठा पायें और कई हद तक इसका सोचना सही भी है क्योंकि अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठायेंगे तो ये हमें बर्बाद कर देगा क्योंकि सरकार ने इसको बहुत शक्ति दे रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये आदमी हमारे सबसे ईमानदार छवि वाले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बदनाम कर रहा है अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो हिमाचल में हमारी भाजपा सरकार को रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जायेगा क्योंकि यह आदमी बद्दी दवा नियन्त्रक जैसे मलाईदार पद पर आने के लिए लालायित रहता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है। जिसकी वजह से हि.प्र. जैसी देवभूमि से 50 प्रतिशत दवा उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं व वापिस हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में पलायन कर रहे हैं।

(A) CS(HP) 95

इसके अतिरिक्त नवनीत मरवाहा ने अपने नाम से कोई भी मकान एवं प्रापर्टी भारत में नहीं खरीदी है। यह व्यक्ति इतना शातिर है कि इसने पहले तो अपने बेटे को कुछ महीने पहले अमेरिका भेज दिया एवं हवाला के जरिये पैसा अमेरिका भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति की रिटायरमेंट मई 2023 में है। यह व्यक्ति रिटायरमेंट के तुरन्त बाद भारत छोड़कर विदेश भाग सकता है क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना पैसा कमाया है कि इसे अपनी पोजिशन की चिन्ता नहीं है। जांच से पहले उक्त व्यक्ति के पासपोर्ट भी जब्त किए जाए। ताकि विदेश न भाग सके।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी

M.C. Jain
Socialist
393, Sector-8
Ambala City-134003.
(M) 9416032020
mcjainsocialist@gmail.com

Copy to:-

1. The President of India, Rashtrapati Bhawan, President's Estate, New Delhi110004.
2. The Chief Justice of India, Supreme Court of India, New Delhi, India.
3. The Director, Central Bureau of Investigation, 6th Floor, Lodhi Road, Plot No. 5-B, Jawaharlal Nehru Stadium Marg, CGO Complex, New Delhi-110003.
4. Sh. Amit Shah, Home Minister of India, Ministry of Home Affairs, Block, New Delhi-110001.
5. The Director, Enforcement, Enforcement Directorate, Lok Nayak Bhawan, 6th Floor, Khan Market, New Delhi-110003.
6. The Governor of Himachal Pradesh, Raj Bhawan, Chotta Shimla, Shimla
7. JAGAT PRAKASH NADDA JI BJP President Central Office 6-A, Pandit Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002 India.
8. Shri Anurag Thakur Singh , 22 AKBAR ROAD , NEW DELHI 110001 .
9. HEALTH MINISTER OF INDIA Room No. 348 'A' Wing, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.
10. PRIME MINISTER SECRETARY GOVT OF INDIA NEW DELHI .
11. HEALTH SECRETARY OF INDIA , NEW DELHI INDIA .
12. DRUG CONTROLLER OF INDIA NEW DELHI INDIA .
13. DEPUTY DRUG CONTROLLER OF INDIA NEW DELHI
14. DEPUTY DRUG CONTROLLER OF INDIA CHANDIGARH RANGE INDIA .
15. DGP OF POLICE HIMACHAL PRADESH STATE POLICE HEAD QUATER SHIMLA INDIA .
16. SP VIGILANCE STATE POLICE HEAD QUATER HIMACHAL PRADESH INDIA .
17. HEALTH MINISTER OF HIMACHAL PRADESH SECRETRIATE SHIMLA INDIA .
18. HEALTH SECRETARY OF HIMACHAL PRADESH SECRETRIATE SHIMLA INDIA .
19. HOME SECRETARY OF HIMACHAL PRADESH SECRETRIATE SHIMLA INDIA .
20. CHIEF MINISTER OF HIMACHAL PRADESH POLITICAL ADVISOR HIMACHAL PRADESH SECRETRIATE SHIMLA INDIA .
21. PRIME MINISTER OF INDIA POLITICAL ADVISOR NEW DELHI INDIA .
22. SP CBI OFFICE CHANDIGARH
23. CHIEF JUSTICE OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA , INDIA .

राज्यपाल ने संस्कृत भारती के 20 दिवसीय संभाषण शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में संस्कृत भारती के माध्यम से आयोजित 20 दिवसीय संभाषण शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा संस्कार की भाषा है। उन्होंने कहा कि योग्य संस्कार न मिलने के कारण समाज में हमारे सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। दुनिया के अधिकांश विकसित राष्ट्रों में अपनी भाषा में ही हर कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश में स्थितियां बदल रही हैं और हमारे समक्ष संस्कृत को पुनःस्थापित करने का सुअवसर है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, इतिहास और परम्परा को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि भाषा सीखने के लिए पुस्तक की नहीं बल्कि संभाषण की आवश्यकता होती है और संभाषण एक कला है, जो सुनकर प्रभावी होती है। उन्होंने राजभवन में इसके सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे तथा विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे संभाषण

शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर संस्कृत भारती के अखिल भारत संगठन मंत्री दिनेश कामत ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत की अधिक उपयोगिता तथा राष्ट्रीय एकता से जोड़कर इसे अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा संस्कृत भाषा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजभवन कर्मचारियों ने संस्कृत में संगीत कार्यक्रम और अपने अनुभव भी साझे किए। पूरे देश में राजभवन स्तर पर आयोजित संस्कृत पर आधारित यह पहला संभाषण शिविर था।

राज्यपाल के सचिव विवेक भाटिया ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

संस्कृत भारत उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार, दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सद्भावना चौक, छोटा शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक विनोद कुमार व होशियार सिंह, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल और पार्षदों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर, मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की कल्पना की थी, जिसमें तकनीकी प्रगति पर विशेष बल दिया गया था। उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में किए गए योगदान को भी याद किया।

राज्यपाल ने जगदीश शर्मा की पुस्तकों का विमोचन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन शिमला में प्रसिद्ध लेखक जगदीश शर्मा की दो

पुस्तकों का विमोचन किया।

राज्यपाल ने जगदीश शर्मा की पुस्तक शक्तिपीठ हिमाचल के संदर्भ में और कविता संग्रह मां और द्वंद्व का विमोचन किया। शक्तिपीठ पुस्तक में उन्होंने हिमाचल के प्रमुख शक्तिपीठों पर शोध कार्य कर तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पुस्तक हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की जानकारी प्रदान करेगी और पाठकों को शोध के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध होगी। उन्होंने लेखक के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर लेखक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

स्थानीय फसलों और उत्पादों को बढ़ावा दें: डॉ शर्मा

शिमला/शैल। ताबो में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (लाहौल और स्पीति-II) की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हाल ही में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के अनुसंधान निदेशक डॉ. रविंदर शर्मा ने की। डॉ. दिवेंद्र गुप्ता, नौणी विवि के निदेशक विस्तार शिक्षा, गुनजीत सिंह चीमा, एसडीएम स्पीति, विभिन्न विभागों के सदस्यों और किसान सदस्यों बैठक में शामिल हुए, जबकि डॉ. राजबीर सिंह, निदेशक, आईसीएआर-अटारी -जोन-I ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।

अपने स्वागत भाषण में डॉ. गुप्ता ने केवीके ताबो द्वारा किए गए कार्यो और स्पीति घाटी के कृषक समुदाय पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए विविधीकरण और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। डॉ. सुधीर वर्मा, केवीके ताबो के प्रभारी ने पिछले वर्ष केवीके द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में बताया और आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डॉ. रविंदर शर्मा ने स्थानीय फसलों और उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट में लोकल तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने के लिए स्थानीय किसानों की

भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जियो इंडिकेटर का उपयोग करने के लिए भी कहा। डॉ. शर्मा ने केवीके संकाय से जौ और गेहूं जैसे स्थानीय फसलों के उत्पादों पर कार्य करने, स्पीति घाटी में उपयुक्ता के लिए मटर के विभिन्न जीनोटाइप का परीक्षण और ट्राइबल खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने स्कूली छात्रों के बीच कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए भी कार्य करने की सलाह दी। सभी सदस्यों ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सब्जी और फलों की नर्सरी, परामर्श प्रदान करने और प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में केवीके के प्रयासों की सराहना की।

प्रतिभागियों ने केवीके के मुख्य फार्म का भी दौरा किया और एचपी-एचडीपी के तहत उच्च घनत्व वाले सेब रोपण पर परीक्षण सहित विभिन्न अनुसंधान परीक्षणों की समीक्षा की। डॉ. शर्मा और डॉ. गुप्ता ने स्पीति के विभिन्न गांवों में किसानों के खेतों में विभिन्न ऑन-फार्म परीक्षणों और फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का दौरा भी किया गया। केंद्र ने स्पीति घाटी के कुरीथ, माने, चिचम और लोसर में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जिसमें सब्जी नर्सरी वितरित की गई।

राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर मंजरी का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वर मंजरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जवाहर लाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला के विद्यार्थियों ने आकर्षक प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं के लिए जाना जाता है तथा प्रदेश का समृद्ध लोक संगीत, नाटय कला और लोक नृत्य भी अपने आप में अनूठे हैं। ललित कला महाविद्यालय इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस चंद्र भूषण बरोवालिया, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर कला प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने हिन्दुजा समूह के अध्यक्ष को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से हिन्दुजा समूह के एक प्रतिनिधिमण्डल ने समूह के पारिवारिक सहयोगी और वरिष्ठ सलाहकार डॉ. एस. के. चड्डा के नेतृत्व में भेंट की।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिन्दुजा समूह भारत के अध्यक्ष अशोक हिन्दुजा से बातचीत की। उन्होंने अशोक हिन्दुजा को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

अशोक हिन्दुजा ने मुख्यमंत्री को विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ बातचीत करने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया।

डॉ. चड्डा ने हिन्दुजा समूह की कम्पनी इंडसइंड बैंक के माध्यम से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में सहयोग करने के लिए राज्य को 90 लाख रुपये के योगदान का एक पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधिमण्डल में हिन्दुजा समूह की सहयोगी कम्पनियों अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल तथा नेक्सट डिजिटल के उच्च अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित मीडिया महामंथन कॉन्क्लेव बात भारत की में भाग लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में दो राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिकाओं पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर (अंग्रेजी) के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बात भारत की विषय पर आयोजित मीडिया महामंथन कॉन्क्लेव के सायंकालीन सत्र में संवाद करते हुए कहा कि भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह गर्व की बात है कि इन दोनों साप्ताहिक पत्रिकाओं ने अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसके

लिए भारत प्रकाशन और आयोजक बधाई के पात्र हैं।

एक दिवसीय बात भारत की कॉन्क्लेव में भाजपा शासित आठ राज्यों उत्तराखण्ड, हरियाणा, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास, आजादी का अमृत महोत्सव, भारत का बहुआयामी विकास और भारत के गौरव से सम्बन्धित अन्य विषयों के साथ पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर की गौरवशाली यात्रा पर प्रकाश डाला गया।

मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक पत्रिकाओं की गौरवशाली यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पांचजन्य के संस्थापक थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1948 में इसके पहले सम्पादक थे। उनके मार्गदर्शन में इन पत्रिकाओं ने अपनी पहचान बनाई और पत्रकारिता की श्रेष्ठता हासिल की। वर्ष 1947 में अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर की शुरूआत की गई।

मुख्यमंत्री ने आम लोगों से जुड़े मुद्दों को खोज कर प्रकाशित करने पर बल देते हुए कहा कि पांचजन्य और अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर ने सच्चे अर्थो में आम लोगों के हितों के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन दोनों प्रकाशनों ने बिना किसी दबाव और प्रभाव के राष्ट्रवाद को प्राथमिकता प्रदान की और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और इन्टरनेट के वर्तमान दौर में समाचारों की कोई कमी नहीं है, परन्तु तथ्यात्मक जानकारी के साथ मूल्य आधारित समाचार प्रस्तुत करना वर्तमान मीडिया के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर पिछले 75 वर्षो से बखूबी अपना काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2021 के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में व्यवसायिकता के उच्च मानकों को स्थापित रखने और अपने काम के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करने वाले सम्मानित मीडिया कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का पहला कर्तव्य है कि वे सामाजिक मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में उजागर करें और लोगों के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा प्रति गैस सिलेण्डर 200 रुपये का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की सराहना की। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों को 12 सिलण्डरों तक सब्सिडी प्राप्त होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल के मूल्य में साढ़े 9 रुपये और डीजल के मूल्य में 7 रुपये की कटौती का भी स्वागत किया। उन्होंने उर्वरक की सब्सिडी के लिए पूर्व में 1.05 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त 1. 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने का भी स्वागत किया।

कॉन्क्लेव में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि वे खबरों में बने रहने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बारे में राजनीतिक दूरदृष्टि के अभाव के कारण हाल ही में आप पार्टी की राज्य इकाई को भंग किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब का राजनीतिक परिदृष्य हिमाचल के परिदृष्य से अलग है और हिमाचल प्रदेश के लोग आप पार्टी के झूठे वायदों में नहीं आएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में कई मील पत्थर स्थापित किए हैं। प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को रसोई गैस एवं धुआं रहित चूल्हा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत उद्यम शुरू करने के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद पर एक करोड़ रुपये के निवेश पर 25 से 30 प्रतिशत तक के उपदान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत 35 प्रतिशत का उपदान प्रदान किया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों को 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हिमाचल पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों से पीड़ित 20 हजार मरीज लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किताबों और पांचजन्य द्वारा राम मन्दिर पर प्रकाशित विशेषांक राष्ट्रीय मन्दिर का भी विमोचन किया।

नौणी विवि टीचर्स एसोसिएशन ने वेतन आयोग की मांग को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन

शिमला/शैल। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टीचर्स एसोसिएशन (यूएचएफटीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी 7वें वेतन आयोग को तत्काल प्रभाव से लागू

करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. रमेश भारद्वाज और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों ने किया। प्रतिनिधिमंडल ने वीसी को अवगत करवाया कि राज्य और विश्वविद्यालयों के अन्य सभी कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग पहले ही लागू किया जा चुका है। हालांकि, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक अभी भी यूजीसी के सातवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी 31 मई, 2022 को होने वाले दौरे की तैयारियों के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम शिमला में आयोजित किया जाएगा तथा

प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को सम्बोधित करना प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंदों की आवश्यकतों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम में इस तरह की 11 चयनित योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअली सम्वाद करेंगे। इनमें देश के 773 ज़िलों के साथ-साथ प्रदेश के 12 जिलों के 40 लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद सत्र में भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि 11 चयनित योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन एवं अमृत, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सम्मिलत है।

राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 11वीं किस्त भी जारी करेंगे।

मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को समुचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित की जाएंगी ताकि लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

प्रशासनिक सचिव एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित थे।

एनवायरो क्विज़-2022 के लिए 3023 विद्यालयों की 5951 टीमों का पंजीकरण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय हिमाचल एनवायरो क्विज़-2022 अन्तर विद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गहरी रूचि दिखाते हुए 3023 राजकीय और निजी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की 5951 टीमों के अन्तर्गत आठवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

उन्होंने बताया कि 20 मई, 2022 को जिला स्तरीय चरण/राउंड का आयोजन वेबसाइट bit.ly/himachalenviroquiz2022 के माध्यम से किया जाएगा तथा पंजीकृत विद्यालयों के साथ 19 मई, 2022 को एक ऑनलाइन लिंक साझा कर प्रवेश पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि 20 मई को जिला स्तरीय राउंड प्रात: 9 से दोपहर बाद 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक टीम को 15 मिनट में 30 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसका परिणाम 21 मई को घोषित किया जाएगा। प्रथम 36 विजेता टीमों को सेमी फाइनल राउंड में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2022 को होने वाली राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत राउंड के लिए चयनित किया जाएगा। इनमें से फाइनल राउंड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम छ: टीमों को प्रमाण-पत्र, ट्रॉफी, आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जबकि सेमी फाइनल तक पहुंची टीमों को भी पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को ई-प्रमाण-पत्र पंजीकृत ऑनलाइन एकाउंट के माध्यम से दिए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं आईटीसी निमायले ईको फ्रैंडली इण्डिया मिशन के सहयोग से आयोजित की जा रही इस राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के व्यक्तिगत राउंड को नैक्सस कन्सल्टिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्विज़ मास्टर वेंकी श्रीनिवासन संचालित करेंगे।

शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है – उसे ज़हर की तरह त्याग दो।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या अब बनेगा भ्रष्टाचार केंद्रीय मुद्दा

जयराम सरकार को प्रदेश में घटे पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच अन्ततः सीबीआई को देनी पड़ी है। क्योंकि अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी करीब आठ लाख की रिकवरी और वाराणसी तथा बिहार के दलालों का पकड़ा जाना ऐसे बिंदु रहे हैं जिनके परिदृश्य में प्रदेश की एसआईटी के लिये इस मामले की जांच कर पाना आसान नहीं रह गया था। फिर प्रदेश उच्च न्यायालय में इस आश्य की एक याचिका भी दायर हो चुकी थी। इसलिए गुड़िया मामले की तर्ज पर उच्च न्यायालय के निर्देश आने से पहले ही सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा है। सी बी आई जांच कब पूरी होती है और उसमें क्या सामने आता है तथा अदालत का उस पर क्या फैसला आता है इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। सरकार यह जांच सीबीआई को देकर अपनी निष्पक्षता का प्रचार कर रही है तो विपक्ष इसे अपने दबाव की जीत बता रहा है। सरकार और विपक्ष के इन दावों में कोई हारा है तो वह है आम आदमी। यह सही है कि इस मामले ने भ्रष्टाचार को चुनावों में केंद्रीय मुद्दा बनाये जाने के स्पष्ट संकेत दे दिये हैं। क्योंकि इस मामले में जयराम के कार्यालय में घटे हर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कर लिया है। प्रदेश में अब तक पेपर लीक के पांच प्रकरण घट चुके हैं। पुलिस में ही जो 2019 के प्रकरण में संलिप्त पाये गये थे उनकी अब भी सक्रिय भूमिका सामने आ गयी है। शिक्षा विभाग में किस तरह से पेपर लीक को प्रश्न पत्रों का जल जाना कहा गया यह जांच में सामने आ गया है। कॉलेज प्रवक्ताओं कि 2017 से कोई भर्ती नहीं हुई है और अब उसके लिए जो पद भरने की अधिसूचना जारी की गयी है उसमें इस भर्ती के मानक प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एच ए एस, एच पी एस, एच एफ एस आदि सेवाओं के लिये निर्धारित किये गये मानकों से अलग कर दिये गये हैं। जयराम सरकार इस दौरान जितने लोग विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त हुये हैं उतने पद भी नियमित रूप से भर नहीं पायी है। यह विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों और उनमें आये उत्तरों के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। पुलिस भर्ती प्रकरण में कांगड़ा के जिस व्यक्ति का नाम चर्चा में आ रहा है उसके संबंध शासन और प्रशासन के शीर्ष में बैठे किन लोगों से हैं यह सवाल आने वाले दिनों में उछलना तय है।

प्रदेश में घटा यह पेपर लीक मामला उस परिदृश्य में और भी संवेदनशील हो जाता है जब यह सामने आता है कि हिमाचल का नाम बेरोजगारी में देश के टॉप छः राज्यों में आ जाता है। यह उस प्रदेश की हालत है जिस पर देश में जनसंख्या के अनुपात में सिक्किम के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने का आरोप लगा था। केंद्रीय वित्त आयोग ने उसका संज्ञान लेकर इसे कम करने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों पर फेयर लान्ज में प्रदेश के अधिकारियों की वित्त आयोग के साथ तीन दिन की बैठक हुई थी। जिसमें दो वर्ष से खाली चले आ रहे पदों को समाप्त करने का फैसला लिया था। विधानसभा में ऐसे फैसले के लिये कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। आज प्रदेश की जो हालत हो गयी है उसमें शासन और प्रशासन के शीर्ष पर बैठे लोगों को पूर्व में घटे इस सब का स्मरण रखना चाहिये था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और प्रदेश कर्ज तथा बेरोजगारी के मुकाम पर पहुंच गया। प्रदेश की जनता इस सब का कैसे और क्या संज्ञान लेगी यह आने वाला वक्त बतायेगा।

इस समय यह सवाल इसलिये अहम हो जाते हैं कि प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा के लिये चुनाव होने हैं और नई सरकार बनेगी। भाजपा सत्ता में वापसी करने के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश का अगला चुनाव जयराम के नेतृत्व में लड़ा जायेगा। क्योंकि भाजपा पुष्कर सिंह धामी और जयराम जैसे युवाओं को भविष्य के नेतृत्व का प्रयोग कर रही है। धामी को हार के बाद भी नेता बना देना और धूमल की हार के कारणों की जांच से साफ इंकार कर देना इसके स्पष्ट प्रमाण है। जयराम पांचवी बार के विधायक हैं और उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। इससे यह माना गया था कि उनके कामकाज में व्यक्तिगत हित कभी प्रभावी नहीं रहेंगे। उनके अपने परिवार के किसी सदस्य का राजनीतिक दखल कभी चर्चा में नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद उनके कार्याकाल में प्रदेश का बहुत अहित हुआ है। जो आज चुनावी वर्ष में पेपर लीक प्रकरण से भाजपा और जयराम दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। यह सवाल जवाब मागेंगे कि प्रदेश का यह कर्ज कहां निवेशित हुआ? मुख्यमंत्री बनने के बाद चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल के 7.19% शेयर के फैसले पर अमल करवाने के दावों का क्या हुआ। इन्वेस्टर मीट के दावों और कई मामलों में श्रेष्ठता के प्रमाण पत्रों के बाद अब कठिन जन योजनाओं के प्रचार के लिये दिल्ली में मीडिया सेंटर स्थापित और प्रचार एजेंसी की सेवायें लेने की व्यवस्था क्यों आयी? क्या नेतृत्व के ऐसे प्रयोग प्रदेश के आम आदमी की कीमत पर किये जायेंगे? शीर्ष प्रशासन के खिलाफ कोई भी कदम न उठा पाने की व्यवस्था क्यों है? निश्चित है कि आने वाले दिनों में भाजपा संघ जय राम और उनके सलाहकारों से यह सवाल पूछे ही जायेंगे। ऐसे में नेतृत्व के ऐसे प्रयोगों से प्रदेश की जनता कितनी देर और भ्रमित रह पायेगी यह देखना दिलचस्प होगा।

इस्लामी इतिहास की सशक्त मुस्लिम महिलाएं, जिन्होंने समाज को मजबूत किया

गौतम चौधरी

इस्लाम का जैसे ही नाम आता है तो महिलाओं के उत्पीड़न का चित्र उभर कर सामने आ जाता है। दरअसल, यह कपोल कल्पना पर आधारित केवल पश्चिमी जगत का प्रचार ही नहीं है अपितु इस्लाम के अनुयायियों में कुछ इन दिनों कुछ ऐसे तत्व उभर कर सामने आ गए हैं, जो महिलाओं के प्रति समारात्मक रवैया नहीं रखते हैं। तालिबान और अल कायदा के साथ ही आईएसआईएसआई जैसे इस्लामिक संगठनों ने अपने करतूतों से इस्लाम को बदनाम किया है। वैसे पैगंबर मुहम्मद साहब के युग में, मुस्लिम महिलाएं खुद को शिक्षित करने के लिए उत्सुक थीं तथा अपना अधिकतम समय वह सीखने में लगाती थीं। पैगंबर की पहली पत्नी, खादीजा अल कुबरा एक सफल व्यापारी और व्यवसायी महिला थीं, जो बेहद अमीर थीं क्योंकि उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में पूर्ण अनुग्रह और गरिमा के साथ अपना व्यवसाय बड़ी क्षमता के साथ चलाया। ये सभी पहलू संभव नहीं होते अगर खदीजा ने व्यवसाय के कौशल को सीखने और खुद को शिक्षित करने के प्रयास नहीं किया होता।

इस्लामी इतिहास में अन्य अनुकरणीय व्यक्तित्वों के नामों में आयशा अबू-बकर, विश्वासियों की मां, खानसा, एक महान कवयित्री शामिल हैं, जो आज तक अरबी साहित्य के बेहतरीन शास्त्रीय कवियों में से एक हैं। फातिमा-ए-फहरी, जो 9वीं शताब्दी में फेज, मोरक्को में कार्बियन मस्जिद की स्थापना की, जो बाद में चलकर शिक्षा और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जैनब अल शाहदा का जिक्र आता है। जैनब, एक प्रसिद्ध फिक्ह (इस्लामी कानून) विद्वान, शिक्षक और 12 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखिकाओं में शुमार थी।

इस्लाम के इतिहास में ऐसी प्रतिष्ठित महिलाओं के कई उदाहरण हैं, जिन्होंने शिक्षा को अपने समाज में सुधार और योगदान के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। अतीत की मुस्लिम महिलाएं प्रेरणादायक रही हैं। उन्होंने इतिहास में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। समकालीन समय में भी, मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, कानून आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई मानक बनाने में सक्षम रही हैं, हालांकि, उन्हें धर्म, सम्मान या राजनीति के नाम पर बार-बार मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया लेकिन, वह अडिग रही। वर्तमान समय में उन्हें दी जाने वाली शिक्षा के कारण यह कम हो गया है।

सच पूछिए तो किसी अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित व्यावसायिक भूमिकाओं को पूरा करना ही व्यक्ति का एकमात्र लक्ष्य नहीं है बल्कि, मुख्य लक्ष्य व्यक्ति और अंततः समुदाय को सशक्त बनाना और सुधारना है। मुस्लिम महिलाओं को उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित किए बिना शिक्षा प्रदान करने और काम करने के लिए समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है।

हिजाब मामले के बाद कुछ अभिभावकों ने बयान दिया है कि वे अपनी बेटियों को बिना हिजाब के स्कूल या कॉलेज नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है बीवी खदीजा (पैगंबर की पत्नी) इस तरह के कृत्यों या फिर ब्यानों से निराश हो सकती हैं। यदि कोई मुस्लिम लड़की शिक्षा प्राप्त करना चुनती है, तो उसे उसकी पसंद के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सशक्तिकरण के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम महिलाओं को आगे आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि इस्लाम महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ है। यदि ऐसा होता तो इस्लामिक जगत में प्रभावशाली महिलाओं की कमी होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।

खास कर भारतीय मुस्लिम महिलाओं को तो आगे बढ़ने में कोई हिचक होनी ही नहीं चाहिए। यहां तो सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जो केवल मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए लाई गयी है। वैसे शिक्षा के बारे में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद में भी कई आयतें दर्ज है। मुस्लिम महिलाओं को उस पर अमल करनी चाहिए न कि उन मौलवियों पर जो नाहक धार्मिक कायदों की गलत व्याख्या करने की कोशिश करते हैं।

प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के रोजगारोन्मुखी प्रयास

शिमला। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (एचपीकेवीएन) के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास और उन्हें स्वरोज़गार के प्रति प्रेरित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। एचपीकेवीएन कौशल गतिविधियों के समन्वय, कार्यान्वयन, तकनीकी व्यवसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।

निगम का मुख्य उद्देश्य तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी), गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का विकास, युवाओं के लिए मांग संचालित कौशल प्रशिक्षण और हिमाचली युवाओं को 100 प्रतिशत लागत मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के रोजगारोन्मुखी प्रयास प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा युवाओं को राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से स्वरोज़गार आधारित व्यवसायों जैसे प्लम्बर, फिटर, बावर्ची, पर्यटन गाइड, कृषि व बागवानी आधारित स्वरोज़गार के अवसरों सहित कई तरह के प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। इन रोज़गारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ-साथ अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। एचपीकेवीएन द्वारा प्रशिक्षण परिणामों की निगरानी एवं मूल्यांकन भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

युवाओं को एचपीकेवीएन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 5 मई, 2022 को शिमला से निगम के जागरूकता वाहन 'कौशल विकास रथ' को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से प्रदेशभर में शैक्षणिक संस्थानों और प्रमुख स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रदेश में अब तक 49727 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला लिया है, जिनमें से प्रशिक्षित 32296 में से 20907 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया जा चुका है। निगम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से तीन साल का बैचलर ऑफ वोकेशन स्नातक कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है, जिसके तहत खुदरा तथा पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में अब तक 4621 अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया है।

प्रदेश के 25 सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के माध्यम से डोमेन और रोजगार कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत सभी सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 6233 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया है।

प्रदेश में उद्योगों का निरंतर विस्तार हो रहा है और इनमें रोज़गार की अपार सम्भावनाएं हैं। युवाओं को उद्योगों में उच्च मांग के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के 9 प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किये गए हैं। इसके तहत अब तक 3100 उम्मीदवारों को नामांकित किया जा चुका हैं।

जो युवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नामांकित नहीं हैं वह भी आईटीआई में एचपीकेवीएन प्रायोजित अल्पावधि प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। इसके तहत प्रदेश के 38 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनएसक्यूएफ सरेखित 3 से 6 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 10413 छात्रों ने अपना नामांकन करवाया है।

एचपीकेवीएन प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भी कार्यान्वित कर रहा है, इसके तहत युवाओं को अनेक रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट में सहायता प्रदान की जा रही है। इसके तहत 16375 युवाओं को नामांकित किया गया है और 11022 को प्रमाणित किया जा चुका है।

प्रदेश में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के उद्देश्य से एचपीकेवीएन द्वारा विशेष अभियान 'नवधारणा' भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से दिव्यांगों को पर्यटन व आतिथ्य और खुदरा क्षेत्र में रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल राज्य के युवाओं की रोज़गार प्राप्त करने की क्षमता में गुणात्मक सुधार कर रहा है, बल्कि उन्हें स्वावलम्बी बनने के लिए भी संबल प्रदान कर रहा है।

ईंधन की कीमतों के मामले में विपक्ष का दोहरा चरित्र

– हरदीप एस पुरी –
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री

2020 की शुरुआत से, दुनिया भर की सरकारें कोविड – 19 महामारी की चपेट में हैं और एक ऐसी उभरती हुई विश्व व्यवस्था के साथ तालमेल बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिसका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है।

भारत सबसे अधिक सहनशील देशों में से एक के रूप में उभरा है। यह एक वास्तविकता है, जो आईएमएफ के नवीनतम विकास अनुमानों में परिलक्षित होती है, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ष 2022 के दौरान 3.6 प्रतिशत की वैश्विक दर की तुलना में, 2022 – 23 में 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी।

मोदी सरकार की दूरदर्शी पहलों की सहायता से, भारत महामारी से पैदा हुई सामाजिक – आर्थिक कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में सक्षम हुआ। अभूतपूर्व 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' जैसे नीतिगत निर्णय ने यह सुनिश्चित किया है कि राष्ट्र एक स्थायी और समावेशी आर्थिक सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दे रही है(टीकाकरण के तहत वैक्सीन की 188 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व में कमी और राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता के बावजूद ऐसा किया गया और यह मोदी सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़ी सभी बातों को स्पष्ट कर देता है।

महामारी के दौरान कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थीं। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाइयों की अस्थिरता के कारण तेल की कीमत में 500 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के बावजूद राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उच्च स्तर जारी रहा। यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा जिम्मेदार शासन और सहकारी संघवाद की लोकनीति के अनुपालन को दर्शाती है। इन कारकों से भारत पर बोझ काफी बढ़ गया, क्योंकि देश अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है।

विदेशी निर्भरता को दूर करने के लिए, भारत अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमताओं में तेजी से वृद्धि कर रहा है। 6 करोड़ से अधिक देशवासी प्रतिदिन खुदरा दुकानों पर पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। देश की आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ रही है। इसके साथ ही खपत में भी वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप, मध्य – अवधि के सन्दर्भ में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति मांग और भी अधिक होगी और यह तब तक जारी रहेगी, जब तक कि भारत एक हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता। इस पृष्ठभूमि में, यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या शासी निकाय उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय उपभोक्ता पर बोझ कम से कम पड़े।

मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके कार्यकाल के दौरान पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि न्यूनतम हो। अप्रैल 2021 और अप्रैल 2022 के बीच, भारत में पेट्रोल की कीमतों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (50.6 प्रतिशत), कनाडा (50. 7 प्रतिशत), जर्मनी (50 प्रतिशत), यूके (58.9 प्रतिशत) और फ्रांस (33 प्रतिशत) की तुलना में सबसे कम थी। डीजल के लिए भी मूल्य वृद्धि में समान अंतर देखा जा सकता है(भारत में सभी प्रमुख देशों की तुलना में सबसे कम वृद्धि हुई है।

घरेलू मूल्य वृद्धि के ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि 2014 – 2022 के दौरान पेट्रोल की कीमत में 36 प्रतिशत की वृद्धि (77 रुपये प्रति लीटर से 105 रुपये प्रति लीटर) पिछले 42 वर्षों के दौरान तुलनात्मक अवधियों में सबसे कम है। पेट्रोल की कीमत में 2007 – 14 के दौरान 60 प्रतिशत (48 रुपये से 77 रुपये), 2000 – 2007 के दौरान 70 प्रतिशत (28 रुपये से 48 रुपये), 1993 – 2000 के दौरान 55 प्रतिशत (18 रुपये से 28 रुपये), 1986 – 1993 के दौरान 125 प्रतिशत (8 रुपये से 18 रुपये), 1979 – 1986 के दौरान 122 प्रतिशत (3.6 रुपये से 8 रुपये) और 1973 – 79 के दौरान 140 प्रतिशत (1. 25 रुपये से 3 रुपये) की वृद्धि दर्ज की गयी थी।

यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल की कीमतों को 2010 में और डीजल की कीमतों को 2014 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। इसका अर्थ है, कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। महामारी के कारण राजस्व घाटे के बावजूद, मोदी सरकार ने नवंबर 2021 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की।

अधिकांश राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती कर कीमत में कमी की, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड जैसे कांग्रेस – सहयोगी राज्यों ने अत्यधिक उत्पाद शुल्क को जारी रखा। यह जानना दिलचस्प है कि विपक्ष, जो मूल्य वृद्धि का विरोध कर रहा है, पूरे भारत में ईंधन पर वैट की उच्चतम दरों को जारी रखने का विकल्प अपनाये हुए है। नीचे दिए गए आंकड़े इस असमानता को रेखांकित और स्पष्ट करते हैं:

महाराष्ट्र 26 प्रतिशत + 10.12 रुपये प्रति लीटर
राजस्थान 31 प्रतिशत + 1.5 रुपये प्रति लीटर
केरल 30 प्रतिशत + 1 रुपये प्रति लीटर
आंध्र प्रदेश 31 प्रतिशत + 5 रुपये प्रति लीटर
तेलंगाना 35 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल 25 प्रतिशत + 13 रुपये प्रति लीटर

प्रधानमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में कई विपक्ष शासित राज्य, पेट्रोल पर राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स के माध्यम से दोगुना राजस्व प्राप्त करते हैं।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) जैसे अन्य महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पाद पर महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा 25 प्रतिशत तक वैट लगाना जारी है, जबकि बीजेपी शासित गुजरात के अहमदाबाद में, वैट सिर्फ 5 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप हवाई यात्रियों पर असुविधाजनक बोझ पड़ता है। बढ़ी कीमतों का लगभग पूरा बोझ यात्रियों पर डाल दिया जाता है (क्योंकि एटीएफ लागत, एयरलाइन परिचालन लागत के लगभग 40 प्रतिशत तक होती है।

विडंबना यह है कि इनमें से कई राज्यों ने शराब और स्पिरिट पर अपने टैक्स कम करने में कोई देरी नहीं की। नवंबर 2021 में, महाराष्ट्र सरकार ने आयातित शराब पर उत्पाद शुल्क को 300 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत कर दिया। आंध्र प्रदेश में शराब पर वैट 130 प्रतिशत और 190 प्रतिशत के बीच लगाया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार ने उसी महीने कम करके 35 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच निर्धारित कर दिया। इससे पहले, अप्रैल 2021 में, राजस्थान सरकार ने बीयर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 34 प्रतिशत से कम करके 31 प्रतिशत कर दिया।

विपक्ष को यह याद रखना चाहिए कि यूपीए सरकार के शासनकाल में 2005 – 12 के बीच 1.44 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दीर्घकालिक तेल बॉन्ड जारी किए गए थे। भारत सरकार पर अब यूपीए – युग के इन तेल बॉन्डों का 3.2 लाख करोड़ रुपये का बोझ है। यूपीए शासन के दौरान लाइसेंस रकबे को रोक दिया गया था, जिससे तेल ईएंडपी का परिचालन बंद हो गया था। वर्षों की अपनी बड़ी विफलताओं, जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है, के बाद मूल्य वृद्धि के बारे में विपक्ष द्वारा शोर – शराबा सर्वथा अनुचित है। इससे भी अधिक दुःखद बात यह है कि भारतीय मीडिया, जिसे विपक्ष के झूठ को उजागर करना चाहिए था, इस झूठे और तथ्यहीन नैरेटिव को समर्थन देकर आगे बढ़ा रहा है।

राष्ट्र – निर्माण के सामूहिक मिशन में पारस्परिकता की अपेक्षा की जाती है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपायों के साथ राज्य सरकारों का समर्थन किया है(जिसमें वित्त आयोग के अनुदान के तहत कर राजस्व का 42 प्रतिशत हिस्सा, शक्ति हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा के लिए अधिक अनुदान और जीएसटी संग्रह का बड़ा हिस्सा शामिल हैं। बजट के तहत राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गयी है। यह ऋण सुविधा राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से राज्य सरकार के उधार को कम करेगी। इसके अलावा, अर्थोपाय अग्रिम राशि (डब्ल्यूएमए) और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के तहत राज्य सरकार न्यूनतम दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस मुद्दे से संबंधित, एक तथ्य यह है कि पिछले आठ वर्षों में ईंधन पर टैक्स के रूप में राज्य सरकारों ने लगभग 15.16 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि कुछ राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को राहत देने की जिम्मेदारी से पीछे हट रहीं हैं। एक ओर, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ईंधन की कीमतों पर झूठी बातें फैला रहा है और दूसरी ओर वे पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम करने से इनकार कर रहे हैं, जो उनके राज्यों में उपभोक्ताओं को अधिक राहत प्रदान करने में योगदान देगा। विपक्ष का यह रवैया दोहरे मापदंड और गुमराह करने वाला है।

सरकार तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियों के प्रति सचेत है और घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए सोच – समझकर निर्णय ले रही है। हमने इस विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, देशवासियों के सामने विज़न की स्पष्टता तथा कार्य में पारदर्शिता रखी गयी है एवं सभी के कल्याण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के नागरिकों द्वारा चुनावी जनादेश लगातार हमारे पक्ष में दिया जा रहा है, जो हमारे कार्यों में उनके विश्वास को परिलक्षित करता है।

भारतः कान्स में विश्व का कंटेंट हब 'कंट्री ऑफ ऑनर' है

अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्री

फ्रेंच रिवेरा के शांत किनारे कान्स फिल्म समारोह के 75वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस साल 'मार्चे डू फिल्म्स' की ओपनिंग नाइट में केंद्र देश के रूप में, भारत वैश्विक दर्शकों को देश की सिनेमाई उत्कृष्टता, तकनीकी कौशल, समृद्ध संस्कृति और कहानी कहने की शानदार विरासत की महक देना चाहता है। भारत और फ्रांस अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं । प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय यात्रा इस संदर्भ में और भी अधिक महत्व रखती है। यह इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है कि भारत को कान्स फिल्म समारोह में मार्चे डू फिल्म में पहले 'सम्मान के देश' के रूप में चुना गया है।

'फेस्टिवल दे कान्स' ने अपनी स्थापना के समय से ही भारत – फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1946 में सफल भारतीय फिल्म निर्माता चेतन आनंद की फिल्म 'नीचा नगर' को पाल्मे डी ओर प्रदान करके प्रारम्भिक कदम रखा गया था और एक दशक बाद 1956 में, सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली ने पाम डी ओर जीता। वर्ष 2013 में, अमिताभ बच्चन को महोत्सव के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था और वर्षों से भारतीय सिनेमा के कई सदस्यों ने कान्स ज्यूरी में काम किया है।

इस साल कान्स में भारत की उपस्थिति कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह पहली बार होगा कि हमारी रेड कार्पेट लाइन न केवल विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधित्व में हमारी सिनेमाई उत्कृष्टता की विविधता को दर्शाती है, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी, जिसमें संगीतकारों और एक लोक कलाकार, जिसने 'युवा और बूढ़े' दोनों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, की भी एक मजबूत उपस्थिति है। भारतीय संगीत के उस्ताद महोत्सव में भारतीय सिनेमा की जीवंतता और विविधता का प्रदर्शन करने के लिए इंडिया पवेलियन में प्रस्तुति देंगे। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप भी इस क्षेत्र के एनीमेशन पेशेवरों के एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल के साथ एवीजीसी यानि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक की दुनिया से सर्वश्रेष्ठ तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित होंगे।

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कई अन्य फिल्मों के साथ 'रॉकेट्री' के विश्व प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार है, जिसे पहली बार कान्स में प्रदर्शित किया जाएगा। एक अन्य पहल में, सत्यजीत रे की पुनः निपुण की गई उत्कृष्ट फिल्म 'प्रतिद्वंदी' को उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर कान्स क्लासिक खंड में प्रदर्शित किया जाएगा।

कान्स में 'भारत का उत्सव' और दुनिया भर में हमारी सिनेमाई उत्कृष्टता की मान्यता देश को 'दुनिया के विषय केंद्र' के रूप में प्रकट करने के लिए तैयार है। आज स्वाद, पसंद और कथा पश्चिम में ईडन से स्थानांतरित हो गई है और पूर्व में बस गई है। भारत की यात्रा को सिनेमा के माध्यम से खूबसूरती से कैद और वर्णित किया गया है और जैसा कि हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' को चिह्नित करते हैं, हमें उस महत्वपूर्ण भूमिका को याद करना चाहिए जो इसने हमारी आजादी की लड़ाई में निभाई और चित्रित की है, चाहे वह अशांत समय और हमारी जीत में हो।

आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारतीय 'रचनात्मक' अर्थव्यवस्था में और विदेशों में भारत की सॉफ्ट पावर को पेश करने में महत्वपूर्ण योगदान है। मोदी सरकार ने भारत में सह – निर्माण, फिल्म की शूटिंग और फिल्म सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्षों में प्रमुख पहल की कल्पना की है और उसका नेतृत्व किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने फिल्म सुविधा नीतियों और सह – निर्माण के अवसर प्रदान करके अग्रणी भूमिका निभाई है। 2018 में, हमने आधिकारिक तौर पर 12 'चौंपियन सेवा क्षेत्रों' में से एक के रूप में दृश्य – श्रव्य सेवाओं को नामित किया था और हाल ही में एक एवीजीसी टास्क फोर्स की स्थापना की थी, जिसमें अग्रनी उद्योगपतियों को शामिल किया गया था, जो इस क्षेत्र में एक लंबा छलांग लगाने के लिए भारत के लिए एक नीति पथ तैयार करेगा और हमें इस क्षेत्र में 'दुनिया का पसंदीदा पोस्ट प्रोडक्शन हब' के रूप में स्थापित करेगा। कुछ हफ्ते पहले, 5900 लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों और विशेषताओं की दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटलीकरण और बहाली प्रक्रिया को हमारी सिनेमाई विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित, और बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया गया था।

हम देख रहे हैं कि भारत के भीतर और दुनिया भर में, मीडिया व्यवसाय और सामग्री निर्माण, उपभोग और वितरण की प्रकृति बदल गई है। एआई का आगमन, वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव जैसे तकनीकी मेटावर्स, भारत के आईटी कुशल कार्यबल के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत में ओटीटी बाजार के 2023 तक सालाना 21% बढ़कर लगभग 12,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आज, भारतीय प्लेटफॉर्म विदेशी लोगों से आगे निकल गए हैं और प्रसारकों के साथ – साथ दूरसंचार कंपनियों के बीच खुद को स्थापित करने की भीड़ है।

भारत अपने कस्बों और गांवों में हलचल मचा रहा है। मुख्यधारा के सिनेमा के साथ – साथ ओटीटी प्लेटफार्मों में – पुरस्कार जीतते हुए, भीतरी इलाकों से हमारी कहानियां और प्रतिभा फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों की कल्पना पर कब्जा कर रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम देश भर में क्षेत्रीय फिल्म समारोह विकसित करने पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनमें से लद्दाख, काशी और जम्मू – कश्मीर का आयोजन किया गया है।

आगे देखते हुए, कोई भी साहसपूर्वक कह सकता है कि भारत आज जो बनाता है, कल दुनिया उसका उपभोग कर रही है। हम एक और छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि लगभग 300 मिलियन नागरिक ऑनलाइन जुड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट (एमएंडई) क्षेत्र के वाणिज्य में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो 2025 तक सालाना 4 ट्रिलियन रुपये उत्पन्न करने की उम्मीद है।

भारत दुनिया को जुड़ने, संवाद करने, बनाने और पसंद के साथ – साथ उपभोग के लिए जो अवसर प्रदान करता है, वह दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसीलिए कहानीकारों का देश आज सिनेमाई दुनिया की सुर्खियों में है।

हर बच्चे को है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अधिकार:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हमीरपुर स्थित एनआईटी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण

आयोग द्वारा आयोजित 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति' विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और उसे यह अधिकार प्रदान करने में सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है।

उन्होंने कहा कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर बातचीत हुई है, लेकिन वास्तव में छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर कोई वास्तविक कार्य नहीं किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को न केवल साक्षर होने बल्कि सही मायने में शिक्षित होने की जरूरत है, जो कार्य एक कमरे में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इस दिशा में बल देती है।

आर्लेकर ने कहा कि व्याकरण के आधार पर कोई भाषा नहीं सिखाई जा सकती। सुनने से ही व्यक्ति भाषा सीखता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रुति पर अधिक बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति को पढ़ने की जरूरत है और इस मामले में सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज गुणात्मक शिक्षा पर चर्चा होती है लेकिन केवल बुनियादी ढांचे का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है।

राज्यपाल ने कहा कि नारी को शिक्षा का अधिकार हमारी प्राचीन संस्कृति में था। उन्होंने कहा कि यहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था जो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता को नष्ट करने के लिए देश में एक बड़ी साजिश रची गई और अंग्रेजों द्वारा लाई गई शिक्षा नीति हमारी राष्ट्रीयता को नष्ट करने वाली थी।

आज इतिहास बदल रहा है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही परिणाम है, जो देश और संस्कृति से जुड़ा है। आर्लेकर ने कहा अगर इस दिशा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आने वाले कल में किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा कि इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है और सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है।

इससे पहले, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेन्द्र बहल ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए आयोग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने एक दिवसीय इस कार्यशाला की जानकारी भी दी।

एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने राज्यपाल का स्वागत किया।

हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक डॉ. कृतिका शर्मा, आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी, विद्या भारती, उत्तर क्षेत्र के सचिव देशराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रो. प्रेम कुमार धूमल को शादी की 50वीं सालगिरह पर शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने प्रो. प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल के स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की है।

इससे पूर्व हमीरपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।

उन्होंने परिधि गृह हमीरपुर में जनसमस्याएं भी सुनीं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने मिट्टी बचाओ अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि मिट्टी हमारे जीवन का आधार है और उपजाऊ मिट्टी अगली पीढ़ी को सौंपना हम सब की जिम्मेवारी है। सद्गुरु द्वारा चलाए गए मिट्टी बचाओ अभियान का समर्थन करने के लिए अपने संदेश में उन्होंने यह बात कही।

उल्लेखनीय है कि मिट्टी को बचाने के लिए अपने अभियान के तहत सद्गुरु 27 देशों से होते हुए 30,000 कि.मी. की अपनी 100 दिन की यात्रा पर हैं।

मुख्यमंत्री ने मिट्टी को बचाने के अभियान में लोगों को साथ लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए सद्गुरू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर तथा अभियान से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सेंट ट्रोपेज़ का भारतीय संपर्क चार पीढ़ियों बाद भी नहीं टूटा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फ्रांस में सेंट ट्रोपेज़ में एलार्ड स्क्वायर

की यात्रा के दौरान, जनरल जीन फ्रेंकोइस एलार्ड और चंबा की उनकी पत्नी राजकुमारी बन्नू पान देई के वंशजों को हिमाचली थाल, टोपी और शॉल भेंट की। राजकुमारी का जन्म हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सेंट ट्रोपेज़ का भारतीय संपर्क चार पीढ़ियों के बाद भी नहीं टूटा है। उन्होंने कहा कि सेंट ट्रोपेज़ में राजकुमारी के परिवार का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों को संरक्षित किया है। मंत्री ने हाल ही में फ्रांस में संपन्न कान फिल्म समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री ने महाराजा रणजीत सिंह (सिख साम्राज्य के पहले महाराजा), जीन-फ्रेंकोइस अलर्ड (महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जनरल) और उनकी पत्नी चंबा की राजकुमारी बन्नू पान देई की आवक्ष प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

वाकनाघाट में उत्कृष्टता केन्द्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबन्ध हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और लैमन ट्री होटल लिमिटेड जेवी ने माइंड लीडर्स

लर्निंग इंडिया के साथ जिला सोलन के वाकनाघाट में पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के संचालन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेटिंग पार्टनर के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

एचपीकेवीएन के महाप्रबन्धक वित्त डॉ. सनील ठाकुर और लैमन ट्री के अधिकारियों विवेक वर्मा और तृप्ता जुनेजा ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

एचपीकेवीएन ने पर्यटन और आत्थिय के 5 क्षेत्रों होटल संचालन और प्रबन्धन, खाद्य और पेय संचालन एवं प्रबन्धन, खाद्य और पेय उत्पादन, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं फिटनेस और वैलनेस में उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र ऑपरेटिंग पार्टनर के रूप में इस प्रतिष्ठित संस्थान को शामिल किया है। यह ऑपरेटिंग पार्टनर लर्निंग एंटरप्राइज मॉडल का उपयोग करके उत्कृष्टता केन्द्र का संचालन करेगा, जिसके माध्यम से उच्च प्रशिक्षण के अतिरिक्त छात्रों को परिसर के भीतर होटल में काम करने, आगंतुकों को सेवा प्रदान करने और सीओई में बिक्री के लिए वाणिज्य उत्पादों का उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। संचालन भागीदार के साथ अनुबन्ध की अवधि मोबिलाइलेशन की तिथि से पांच वर्ष तक की होगी।

इस अवसर पर महाप्रबन्धक (प्रशिक्षण) हर्ष अमरेन्द्र सिंह, सेक्टर विशेषज्ञ (प्रशिक्षण) कपिल भारद्वाज और एससीएफ नरेश चौहान भी उपस्थित थे।

पेट्रोल व डीज़ल की कीमतों में कमी लोगों को रिझाने का असफल प्रयास:हर्ष महाजन

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने पेट्रोल व डीज़ल पर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 व 6 रुपये की कमी को महज एक ड्रामा करार देते हुए कहा है कि सरकार एक तरह इसके मूल्यों में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी करती है और जब किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते है तो इसमें दो चार रुपये की मामूली कटौती कर लोगों को रिझाने का असफल प्रयास करने की पूरी कोशिश करती है।

हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2014 में यूपीए सरकार के समय 76 रुपये पेट्रोल व 54 रुपये डीज़ल का मूल्य था, जबकि अप्रैल 2022 में पेट्रोल 106 रुपये व डीज़ल 89 रुपये की दर से बेचा गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 22 मार्च 2022 से 4 अप्रैल के बीच इसके मूल्यों में क्रमश 10 रुपये पेट्रोल में और 9 रुपये डीज़ल में बढ़ोतरी की। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 8.50 रुपये व डीज़ल में 6.40 रुपये की कमी कर कोई बड़ी राहत लोगों को नही दी है।

हर्ष महाजन ने आरोप लगाया कि पहले सरकार अपना खजाना भरा और उसके बाद मामूली सी कटौती कर इसे जन कल्याण का नाम दिया जा रहा है, जो लोगों के साथ सरासर एक बड़ा धोखा है।

हर्ष महाजन ने एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर भी चिंता जताते हुए कहा है कि मोदी सरकार एक हाथ दे रही है तो दूसरे हाथ लेने में जुटी है। उन्होंने कहा कि उज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर में 200 रुपये की सब्सिडी मात्र इनके लाभ्यार्थीयों को लुभाने का एक असफल प्रयास है क्योंकि गरीब परिवारों ने अब गैस सिलेंडर का उपयोग करना ही बंद कर दिया है।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद् की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वानाथ आर्लेकर जो हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ने परिषद की आय के स्त्रोत बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने परिषद को अपनी गतिविधियों में

आजीवन सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।

राज्यपाल राजभवन में हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर संसाधन जुटाने के लिए उपायुक्त सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मन्दिरों को प्राप्त होने वाली आय और निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड से भी यह सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद को एक विभाग की तरह संचालित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मन्दिर न्यास, परोपकारी संस्थाओं सहित समाज के समृद्ध वर्गों को आगे बढ़कर चैरिटेबल गतिविधियों के माध्यम से इस संस्थान के फंड और संसाधनों को बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी आश्रमों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसे एक सामाजिक संगठन के तौर पर लिया जाना चाहिए, ताकि इसकी गतिविधियों में समाज को भी जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि परिषद् के सभी सदस्यों को स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने परिषद् की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि सेवा भावना को बनाए रखते हुए सामूहिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के दृष्टिगत अन्य सामाजिक संगठनों को भी इससे जोड़ना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में उपायुक्तों एवं उनकी टीम द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे परिषद् की गतिविधियों को भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रखेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद् शीघ्र ही आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगी।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि एक बालक की क्षमता के समग्र विकास के लिए प्रत्येक बच्चे को समान अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। आश्रम में बालकों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जानी चाहिए जो अन्य बालकों को उनके घरों में उपलब्ध रहती हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की मदद वास्तव में मानवता और धर्म की सच्ची सेवा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने सम्बोधन में परिषद के बेहतर संचालन के लिए निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को सक्रिय सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को परिषद से आजीवन सदस्य के रूप में जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि परिषद के आजीवन सदस्यों के सदस्यता शुल्क को पांच हज़ार से बढ़ाकर 11 हज़ार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देव भूमि होने से प्रदेशवासियों में मानवीय सोच की अधिकता के कारण राज्य में परिजनों द्वारा अभिभावकों एवं वृद्धजनों के परित्याग के मामले कम सामने आते हैं। इसके बावजूद प्रदेश के वृद्धाश्रमों में अभी भी कुछ संख्या में वृद्धजन रह रहे हैं। उन्होंने वृद्ध आश्रमों एवं अनाथालयों के समुचित प्रबन्धन पर बल दिया ताकि यहां रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जय राम ठाकुर ने कहा कि परिषद् को आम लोगों और परोपकारी संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के प्रबंधन में सहयोग के लिए आगे आने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए औद्योगिक घरानों को भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण विभाग के पास पीड़ित मानवता की सेवा का बेहतर अवसर रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे आश्रम संचालित कर रहे संगठनों की हर सम्भव मदद करेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग निराश्रित बच्चों, विशेष रूप से सक्षम और बुजुर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

पुलिस भर्ती मामले की जांच किसी सिटिंग जज से करवायी जाये:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती मामलें में सरकार व प्रशासन की विफलता की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिसे

हल्के में नही लिया जा सकता। इस पूरे मामलें की जांच तुरंत पूरी कर इसके असली गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इस घटना से प्रदेश की स्वच्छ छवि पर दाग लगा है।

जिला मुख्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने आयी प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारों के साथ हो रहें अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेगी।

प्रतिभा सिह ने कहा कि भाजपा के इस शासनकाल में देश प्रदेश बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा के नेता कभी कोई बात नही करते। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम मनमर्जी से बढ़ाये जा रहें है। लोगों को बढ़ती महंगाई से कोई भी राहत नही दी जा रही है।

प्रतिभा सिंह ने इस मामलें की सीबीआई जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच किसी सिटिंग जज से करवायी जाये। उन्होंने कहा कि डीजीपी को क्लीन चिट देना मामले को रफा दफा करने की कोशिश लगती है।

प्रतिभा सिंह ने इसके उपरांत गेयटी थियेटर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की स्मृति में लगाई गई फ़ोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिह भी साथ थे। उन्होंने इस फ़ोटो प्रदर्शनी को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इसके आयोजकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से स्व राजीव गांधी के जीवन की यादें रखी गई है जो बहुत ही स्मरणीय है।

शिक्षा के मामले में केरल से मुकाबले में है हिमाचल, दिल्ली कहीं नहीं :रणधीर

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिमला में पूर्व

नियोजित कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां कार्यक्रम और प्रश्नों का निर्णय पहले ही कर लिया गया था।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह के ड्रामे को बंद करना चाहिए, जिसके जरिए वे आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में केवल आप सदस्य मौजूद थे और मनीष सिसोदिया के साथ बातचीत में शामिल थे। सिसोदिया द्वारा लगाये गये सभी आरोप निराधार और बिना दस्तावेज के हैं।

उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में हिमाचल पहले स्थान पर है और हमें हिमाचल की शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। हम केवल केरल के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और हमारी साक्षरता दर 96% से अधिक है। हम मनीष सिसोदिया से पूछना चाहेंगे कि शिक्षा के मामले में दिल्ली कहां है, दिल्ली हिमाचल से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया द्वारा पेश किए गए सभी तथ्यों और आंकड़ों मनघड़ंत है।

हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य में उच्च शिक्षा के 6 लाख छात्र हैं और शिक्षा के सभी स्तरों पर हिमाचल में 14 लाख से अधिक नामांकित हैं।

रणधीर ने कहा कि मनीष सिसोदिया के सभी दावे केवल राजनीतिक फायदे के लिए हैं।

हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारी सरकार ने हमारे कई गैर-नियमित शिक्षकों को नियमित किया है।

हमारा राज्य पूरे राज्य में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे रहा है जिसके लिए हमारे पास 15 करोड़ का बजट है। हमारी सरकार हमारे राज्य में छात्रों को मुफ्त पोशाक, किताबें और बैग दे रही है।

हिमाचल और दिल्ली की तुलना नहीं की जा सकती है, हमारी अलग-अलग भौगोलिक स्थितियां हैं।

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा राज्य है जहां 5 छात्रों के लिए स्कूल खोलना है क्योंकि बच्चों को लंबी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (एचपीयू) और कॉमनवेल्थ ऑफ पेनसिल्वेनिया, स्टेट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन (यूएसए) विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा अकादमिक साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

वर्चुअल मोड एग्रीमेंट साइनिंग समारोह में डॉ. पीटर गारलैंड, कार्यकारी कुलपति एमेरिट्स, पेंसिल्वेनिया स्टेट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, जेम्स स्ट्रूज़ी, स्टेट सीनेटर, पेनसिल्वेनिया, डॉ. डोना विल्सन, वाइस चांसलर फॉर एकेडमिक एंड स्टूडेंट अफेयर्स, चीफ एकेडमिक ऑफिसर, पेनसिल्वेनिया स्टेट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, डॉ. माइकल ड्रिस्कॉल, प्रेसिडेंट, इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया (आईयूपी), डॉ. लारा लुएटकेहंस, प्रोवोस्ट और वीपी ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, आईयूपी, प्रतिनिधि कनिका चौधरी उपस्थित थीं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) जनादेश के माध्यम से शिक्षा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और आईयूपी के बीच संबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने

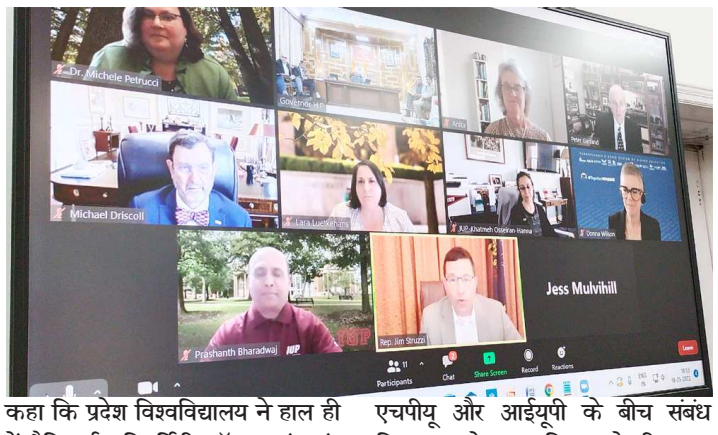

कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाल ही में हैरिसबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और फोरेंसिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के संबंध में अच्छी प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और आईयूपी के बीच समझौता ज्ञापन सभी हितधारकों के परिवर्तन और समावेशी विकास की आवश्यकता को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर विविध समुदाय तक पहुंचाने में मदद करेगा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने कहा कि एचपीयू और आईयूपी के बीच संबंध विशुद्ध रूप से अकादमिक साझेदारी, उच्च शिक्षा के लिए समन्वय और सहयोग के लिए महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, भारत और कॉमनवेल्थ ऑफ पेनसिल्वेनिया, यूएसए के उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर, उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम (मास्टर डॉक्टरेट) शामिल हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या जयराम हटाये जा रहे हैं धूमल

परिवार के आयोजन के बाद उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं पंजाब में भाजपा की हार और आम आदमी पार्टी की जीत ने भाजपा तथा कांग्रेस दोनों के लिए ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है कि दोनों दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस संगठन में हुआ बदलाव उसी का परिणाम है। अब पंजाब की मान सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जिस तेजी से कारवाई की है उससे भी हरियाणा और हिमाचल की भाजपा सरकारों पर दबाव आया है। हिमाचल में जब से जयराम सरकार आयी है तब से लेकर आज तक कई मंत्रियों को लेकर बेनामी पत्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामले उठते रहे हैं। लेकिन किसी पर कोई कारवाई नहीं हुई है। बल्कि पत्रों को लेकर कुछ पत्रकारों को अवश्य परेशान किया गया। सरकार के पांच वरिष्ठ अधिकारी एक ही समय में दिल्ली और शिमला में मूल पोस्टिंगज लेकर दोनों जगह सरकारी आवासों का लाभ लेने के साथ ही विशेष वेतन का भी लाभ ले रहे हैं। नियमों के मुताबिक यह अपराध जिस पर तुरंत कारवाई होनी चाहिये थी। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पा रही है। हर गलती को कांग्रेस शासन के साथ तुलना करके दबाया जा रहा है। जनता में यह सब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी जमीनी सच्चाई का परिणाम है कि अब तक हुये चारों चुनावी सर्वेक्षणों में किसी में भी भाजपा जीत के आस पास भी नहीं है। यह सर्वेक्षण तब हुये हैं जब पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला नहीं घटा था और न ही भाजपा का गुटों में बंटा होना सामने आया था। अब जब भाजपा ने पुष्कर धामी को हारने के बाद भी फिर से मुख्यमंत्री बना दिया तो धूमल की ओर से भी उनकी हार के कारणों की जांच की मांग आना स्वभाविक था। क्योंकि जयराम के वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज का यह ब्यान आ चुका था कि 2017 में पुराने नेतृत्व और नीतियों को खत्म करके नया नेता तथा नीति लायी गयी है। भारद्वाज के इस ब्यान पर नड्डा ने यह कह कर मोहर लगा दी कि भाजपा गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। नड्डा ने यह स्पष्ट कह दिया कि हार के कारणों की जांच नहीं की जा सकती। जयराम के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाने का ऐलान कर दिया। संयोगवश नड्डा के इस ऐलान के बाद ही केजरीवाल की दो प्रदेश यात्राएं हुई। दोनों रैलियां सारे अवरोधों के बावजूद सफल रही। केजरीवाल की रैलियों का प्रभाव कम करने के लिये नड्डा को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन शिमला और कांगड़ा दोनों जगह केजरीवाल के मुकाबले भीड़ बहुत कम रही। अब इस सभी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री की यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। युवा मोर्चा का राष्ट्रीय आयोजन धर्मशाला में किया गया। यह चर्चाएं सामने आयी हैं कि बड़े स्तर पर टिकटों में परिवर्तन होगा। अनचाहे ही यह संदेश चला गया है कि धूमल खेमें के पर कतरने का पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है।

लेकिन संयोगवश इन्हीं दिनों धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह का अवसर आ गया। धूमल पुत्रों ने इस अवसर को एक बड़े आयोजन का रूप दे दिया। इस अवसर पर जिस कदर जनता अपने नेता के साथ इकटठी हो गयी उसने भाजपा के भीतर पक रहे सारे षडयंत्रों की हवा निकालते हुये यह प्रमाणित कर दिया कि प्रदेश की राजनीति के सारे समीकरणों को बदलने की ताकत अब भी इस परिवार के पास है। इस आयोजन को राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरह से नड्डा के उस ब्यान का जवाब मान रहे हैं जिसमें नड्डा ने कहा था कि पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला लेती है। आज जिस तरह से जयराम सरकार ने धूमल को हाशिये पर धकेल रखा है उस परिदृश्य में इस परिवार के परिवारिक आयोजन में इतने लोगों का आ जाना राजनीतिक पंडितों के लिये बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। क्योंकि जयराम के सलाहकारों ने उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वह चाह कर भी अपने में कोई सुधार नहीं कर सकते। ऐसे में पार्टी को शर्मनाक हार या नेतृत्व परिवर्तन करके जीत की संभावनाओं तक पहुंचने के प्रयासों में से एक को चुनने की बाध्यता आ खड़ी हुई है। दूसरी ओर धूमल परिवार को भी भविष्य में स्थापित करने के लिये यह वस्तुस्थिति एक बड़ी चुनौती बन गयी है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों के नेतृत्व में परिवर्तन करना अब बाध्यता बन गयी है और अब शायद नड्डा का संरक्षण भी रक्षा नहीं कर पायेगा।

सिसोदिया की शिमला यात्रा के बाद भी नहीं हो पाया आप की इकाई का पूर्णगठन

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी अभी तक प्रदेश इकाई का नये सिरे से गठन नहीं कर पायी है। केजरीवाल की यात्राओं और सत्येंद्र जैन के प्रयासों से भी इस दिशा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पायी है। लेकिन दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया की यात्रा के बाद प्रदेश में शिक्षा की हालत एक मुद्दा अवश्य बन गयी है। सिसोदिया द्वारा उठाये गये सवालों की चपेट में पूरी जयराम सरकार आ गयी और जवाब देने पर विवश भी हो गयी है। यही नहीं सिसोदिया ने आप की घोषणाओं को पूरा करने के लिये साधन कहां से आयेंगे इसका जवाब देते हुए कहा है कि यह सब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके हो सकता है। भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुये स्पष्ट जिक्र किया कि प्रदेश का एक नेता मंत्री बनने से पहले एक साधारण तीन कमरों के मकान में रहता था लेकिन मंत्री बनने के बाद जब वह अपने बेटे की शादी की दस-दस रिसेप्शन दिल्ली और शिमला के बीच दे तो तय है कि यह हैसियत भ्रष्टाचार से ही आयी है। सिसोदिया ने मंत्री का नाम लिये बगैर भाजपा के उन तीनों बड़े नेताओं पर जनता का ध्यान केंद्रित करवा दिया जिन्होंने इस दौरान अपने बेटों की शादियां की है। आप सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कितनी गंभीर है इसका परिचय भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त और गिरफ्तार करके दे दिया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के सौदों में 1% कमीशन मांगे जाने की सूचना केवल मुख्यमंत्री के ही पास थी और सार्वजनिक नहीं थी। लेकिन हिमाचल में ऐसी सूचनाओं के सार्वजनिक होने के बावजूद भी किसी नेता के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। पंजाब की आप सरकार के इस तरह के कदमों से हिमाचल में भी आम आदमी की विश्वसनीयता बनने में एक आधार तैयार हो रहा है। लेकिन इसी कदम के साथ हिमाचल में

भी भाजपा से निकलकर आप में शामिल हुये नेताओं पर चर्चा आ सकती हैं क्योंकि संघ की सक्रिय पृष्ठभूमि से निकलकर दूसरे दलों में गये नेताओं की पहली निष्ठा संघ में ही रहती है। जबकि आज की बुनियादी समस्याओं के लिये संघ की वैचारिकता ही सबसे बड़ा कारण है। 1980 में जनता पार्टी इसी दोहरी निष्ठा के कारण टूटी थी। प्रदेश की आप इकाई में सिसोदिया के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर आप के दो ग्रुपों में झगड़ा होने के वीडियो जिस तरह से वायरल हुये हैं उससे यह आशंका बराबर बन गयी है कि आने वाले दिनों में ऐसे झगड़े पार्टी के आकार लेने से पहले ही उसके लिए कोई कठिनाइयां न खड़ा कर दें। क्योंकि ऐसा झगड़ा होने की यह दूसरी घटना है। इसके लिए पार्टी में संयोजक का बनाया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर भाजपा और कांग्रेस को एक साथ घेरना आवश्यक है। लेकिन अभी तक प्रदेश के नेता उसी पाठ को दोहरा रहे हैं जिसकी इबारत उन्हें दिल्ली से लिखकर दी जा रही है। इस समय सोशल मीडिया में पार्टी के लिये वह लोग पोस्टे डाल रहे हैं जो इसके लिये अधिकृत ही नहीं है। बल्कि उनकी पहली निष्ठांये आज भी भाजपा के साथ हैं। ऐसे में आप के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आप के लिये जो भी व्यावहारिक आधार तैयार किया जा रहा है उस को आगे बढ़ाने के लिये जब तक स्थानीय स्तर पर कोई सक्षम लोग नहीं होंगे तब तक कोई ज्यादा परिणाम सामने नहीं आयेंगे। जब तक प्रदेश इकाई की पूर्ण घोषणा नहीं हो जायेगी तब तक यह आरोप लगता ही रहेगा कि कहीं पार्टी अंत में अपरोक्ष रूप में भाजपा को ही मजबूत करने का ही प्रयास तो नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक सिराज में रोड शो और रैली करने की तारीख घोषित नहीं हो पायी है।